

## इस सप्ताह साठ वर्ष पूर्व चर्चिल की मृत्यु हुई थी

क्या यह सही समय नहीं, आज हमारे गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ के दिन चर्चिल की भारत के मुताल्लिक भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए?

- अंजन राय -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 जनवरी। पिछले कुछ समय से, सर विंस्टन चर्चिल के जीवन और समय में बहुत रुचि बढ़ी है, जिनका साठ वर्ष पूर्व, 24 जनवरी 1960 को निधन हो गया था।

भारत के गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर, उस काल के ऐतिहासिक व्यक्तियों की भूमिकाओं पर नए दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं, जब भारत उपनिवेश से एक सम्प्रभु राज्य में परिवर्तित हो रहा था।

भारतीय दृष्टिकोण से, क्लैमेंट एटली चर्चिल जितने महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में दिखाई पड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में एटली ने समय की जरूरतों को कहीं अधिक गहराई और समझदारी से महसूस किया था, जबकि, चर्चिल "सैलफ आब्लैस्ड" थे।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 1950 के दशक की शुरुआत में, बी.वी.सी. के साथ एक इंटरव्यू में भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्त करने के एटली के फैसले के संदर्भ में बात की थी। हालांकि, उन्हें उस समय एटली के

भारत के दृष्टिकोण से चर्चिल के बाद इंग्लैंड के प्र.मंत्री बने क्लैमेंट एटली की भूमिका ज्यादा समझदारीपूर्ण व समय संगत थी।

द्वितीय विश्व के हीरो विंस्टन चर्चिल भारत को ब्रिटेन के साम्राज्य का हिस्सा बनाए रखने की कल्पना में ही बसर कर रहे थे, जबकि एटली भारत से इंग्लैंड की सम्मानजनक वापसी को विकल्प मान रहे थे।

एटली ने 1920 के दशक में हिन्दुस्तान का विस्तार से दौरा किया था तथा स्वतंत्रता आंदोलन का जमीनी असर देखकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने की व्यवहारिकता को पहचाना था।

एक मत यह भी है, चर्चिल भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गंभीरता को समझ नहीं पाये, बल्कि, भारत के प्रति असंवेदनशीलता का कलंक भी उन पर 1942, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगा था।

चर्चिल ने बंगाल के लिये भेजे गये अनाज से भरे जहाजों को "डाइवर्ट" करके ब्रिटिश सेना की खपत के लिये भेजने का निर्णय लिया था, जिससे "ग्रेट बंगाल फैमिन", बंगाल में भारी भूखमरी फैली थी।

निर्णय का कारण स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने महसूस किया था कि इस

संदर्भ में एटली की "स्टेटमेंटेशन" की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।

ब्रिटेनवासी जहां आजकल चर्चिल की जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, वहीं यह भी बता दें कि चर्चिल के दिलों दिमाग पर भारत एक जुनून की तरह छाया हुआ था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिली चुनावी हार के बाद, जब वो सत्ता में नहीं थे, तब भी चर्चिल भारत को इंग्लैंड के अंग के रूप में देखते थे। वो किसी भी हाल में "भारतीय संपत्तियों" से जुड़े रहना चाहते थे।

इस दृष्टिकोण से युद्ध खत्म होने तक चर्चिल "आउटडेटेड" हो गए थे। चर्चिल के बाद प्रधानमंत्री बने क्लैमेंट एटली बदलते समय के साथ तालमेल बिटाने वाले आधुनिक सोच वाले व्यक्ति थे। वे समझ गए थे कि सम्मानजनक तरीके से भारत छोड़ देना ही एक मात्र विकल्प है। हालांकि ब्रिटेन की भारत से वापसी की प्रक्रिया काफी अस्थिर थी और भयावह रही लोग इसमें मारे गए।

भले ही चर्चिल की चार हीरो के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। शनिवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली तथा सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दूसरा सर्वोच्च अवार्ड "पद्म विभूषण" प्रदान करने की घोषणा की गई। इसी प्रकार, मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड जॉर्ज फर्नांडीज तथा उडुपी के आध्यात्मिक गुरु विश्वेपातीर्थ स्वामी को देने की घोषणा की गई। मणिपुर की स्पोर्ट्स स्टाफ एम.सी. मैरी कोम,

जॉर्ज फर्नांडिस (मरणोपरांत), मैरीकोम, स्वामी विश्वेश तीर्थ, छत्रलाल मिश्र और ए.जुगनाथ (मॉरिशस) को भी पद्म विभूषण दिया गया है।

मॉरिशस के अमेरुद जुगनाथ तथा उत्तर प्रदेश के छत्रलाल मिश्र को पद्म विभूषण दिये जाने की भी घोषणा भी की गई है।

देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में उपरोक्त सात पद्म विभूषण पुरस्कारों के अतिरिक्त 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं, दस विदेशी, एन.आर.आई., पी.ई.ओ. और ओ.सी.आई. श्रेणी के हैं। तेरह हस्तियों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं।

## तुरंत प्रभाव से विदेशों को मदद के सभी प्रस्ताव व कार्यक्रम स्थगित किये

अमेरिका के विदेश मंत्रालय के इस आदेश में केवल दो अपवाद मंजूर किये गये हैं, मिस्र इजरायल व मित्र को दी जाने वाली सहायता के प्रस्ताव

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के एक आदेश पर शुक्रवार को मौजूदा सभी विदेशी सहायता के लिये "स्टॉप वर्क" आदेश जारी कर दिया गया। यह कदम राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के एक आदेश की अनुपालना में उठाया गया।

स्टेट डिपार्टमेंट के फॉरेन एडवोकेट द्वारा जारी किये गये तथा सैक्रेटरी ऑफ स्टेट, मार्को रूबियो द्वारा अनुमोदित केवल में कहा गया कि इजरायल तथा मित्र के सैन्य वित्तीय पोषण के लिए छूट दी गई है। इनके अलावा, केवल में किसी अन्यदेश का उल्लेख नहीं किया गया है। सोमवार को, अपना पद संभालने के कुछ घंटे बाद ही, ट्रम्प ने विदेशी विकास सहायता को 90 दिन के रोकने के आदेश दिये थे। इस बीच, उनकी विदेश नीति की क्षमताओं और जारी रखे जाने की समीक्षा लम्बित रहेगी।

लेकिन इस आदेश के क्षेत्र की जानकारी तुरन्त नहीं मिल सकी थी तथा यह अस्पष्ट था कि कौन-कौन सी फंडिंग रोकें जायेंगी, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस संघीय सरकार का

आदेश के अनुसार, सैक्रेटरी ऑफ स्टेट (विदेश मंत्री) मार्को रूबियो अगले 85 दिनों में अमेरिका द्वारा विदेशों में दी जा रही सहायता की सार्थकता व इफैक्टिवनेस का मुआयना करेंगे तथा फिर इस मूल्यांकन के बाद निर्णय लेंगे कि किन देशों को किन-किन प्रोग्रामों के अंतर्गत सहायता दी जाये या नहीं।

जैसा कि विदित ही है, राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की थी कि अमेरिका द्वारा विदेशों को दी जा रही सहायता को 90 दिन "स्टॉप वर्क" के आदेश से स्थगित किया जायेगा। ट्रम्प की इस घोषणा के अंतर्गत अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अन्य देशों को दी जा रही सहायता के मुताल्लिक यह स्थगन आदेश निकाला है।

बजट तैयार करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रम्प का उक्त आदेश गैर कानूनी है क्योंकि इस कांग्रेस में चुनौती मिलना तय है।

एक विशेषज्ञ ने अपना नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा, "इन अंतर्राष्ट्रीय निवेशों को फ्रीज कर देने से हमारे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर इसकी पूर्ति के लिये फंडिंग पार्टनर तलाश करेंगे, जो या तो अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा रखने वाले होंगे या उसके विरोधी। तथा जब तक यह गैर कानूनी रोक जारी रहेगी, वे

देश अमेरिका के प्रभाव की जगह जरूरतमंद देशों पर अपना प्रभाव कायम रखेंगे।"

स्टेट डिपार्टमेंट का मौमो, जो तत्काल प्रभावी हो गया है, में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी "यह सुनिश्चित करेंगे कि, कानून के अंतर्गत अधिकतम सोमा तक, विदेशी सहायता के लिये तब तक और कोई नया अनुबंध नहीं किया जायेगा", जब तक रूबियो, समीक्षा के बाद, कोई निर्णय नहीं ले लेते। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू करने की तैयारी

राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू करने की घोषणा की

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। मध्य प्रदेश, मध्य-निषेध क्लब में शामिल होने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की घोषणा कर दी है। इस कदम को पूर्ण शराबबंदी की दिशा में एक चरणबद्ध तरीका माना जा सकता है। इस समय गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम में शराब पर रोक लगी हुई है। इसके अलावा, केन्द्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी शराब पर आंशिक पाबंदी है। कई राज्यों ने इससे पहले भी शराबबंदी कानून लागू किया, लेकिन बाद में इसे अव्यवहारिक होने के कारण पर निरस्त कर दिया। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मणिपुर, मिजोरम तथा तमिलनाडु शामिल हैं।

मध्य-निषेध लागू करने वाले राज्यों में, महिलाओं के खिलाफ होने वाली

इस समय चार राज्यों में पूर्ण शराबबंदी है। गुजरात, बिहार, नागालैंड और मिजोरम।

पूर्ण शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या घटी है, पर, अवैध शराब का बाजार तेजी से पनपा है।

यही नहीं, इन राज्यों में दूषित शराब पीने के मामले भी देखे गए। गुजरात में ऐसे ही एक हादसे में जुलाई 2022 में 42 लोग मारे गए थे। गत वर्ष बिहार के सिवान व सारन में भी ऐसे दो हादसे हुए।

हिंसा की घटनाओं में कमी आने की खबरें हैं। लेकिन शराबबंदी के कारण शराब का गैरकानूनी उत्पादन बढ़ा है तथा प्रदूषित मैथेनॉल के कारण लोगों की मौतें हुई हैं। जुलाई 2022 में, गुजरात में इस कारण कम से कम 42 लोग मर गये तथा 97 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। पिछले वर्ष, बिहार के सिवान तथा सारन जिलों में देशी शराब दुखान्तिका में 35 से अधिक लोग मर गये थे। जहाँ मद्य-निषेध नीति के लाभ साफ जाहिर हैं, वहीं इस प्रकार की नीतियों के नकारात्मक प्रभाव के बारे में प्रतिकूल तर्क भी दिये जाते रहे हैं। विभिन्न राज्यों, जिनमें बिहार और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

### अवकाश की सूचना

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रदूत कार्यालय में अवकाश रहेगा। अंतः अगला अंक 28 जनवरी को प्रकाशित होगा। -प्रधान सम्पादक

### साधुओं के मन की बात

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात से प्रेरित "साधुओं के मन की बात" नामक एक विशेष कार्यक्रम शनिवार को महाकुंभ

महाकुंभ में शनिवार को "साधुओं के मन की बात" कार्यक्रम हुआ, इसमें साधु-संतों ने सनातन धर्म पर अपने विचार व्यक्त किये।

में आयोजित किया जायेगा। इस कार्यक्रम में, 10,000 संत महाकुंभ पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यह कार्यक्रम साधुओं को सनातन धर्म के मुख्य पहलुओं पर अपने विचार साझा करने का एक मंच उपलब्ध करायेंगा।

76 गणतंत्र दिवस

गणतंत्र दिवस पर विकसित व परम वैभवशाली भारत बनाने का संकल्प लें।

विदेशियों द्वारा भारत माता की लूट

ऑक्सफैम ग्लोबल यूके एक विश्व प्रसिद्ध संस्था के द्वारा हाल ही में एक सर्वे आया है कि 1765 से लेकर 1900 के बीच में ब्रिटिशर्स ने 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की है। इससे पहले और बाद की अंशेजों, पुर्तगालियों, डचों, हूण, शक एवं मुगलों की लूट का आंकड़ा इसमें सम्मिलित नहीं है। 1000 वर्षों की लूट को यदि औसत रूप में भी देखें तो यह कम से कम 100 ट्रिलियन से ऊपर होगी। देश की सकल अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से यदि लूट को 25% माने तो भारत की कुल अर्थव्यवस्था 500 साल पहले अनुमानित 500 ट्रिलियन रही होगी।

ये भारत की परम समृद्धि का विदेशी संस्थाओं द्वारा दस्तावेजों के आधार पर आंकलन है। हम चाहते हैं लूट के इन सत्यों एवं तथ्यों का बोध सब भारतवासियों को हो और आगे हम भारत माता को इन विदेशी ताकतों की लूट से बचाने के लिए संकल्पित एवं संगठित होकर आज से ही स्वदेशी का व्रत लें। स्वदेशी के इस महायज्ञ में पतंजलि भी अपनी एक विनम्र सेवा राष्ट्र को समर्पित कर रहा है।

विदेशियों ने तो मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स की लूट की है और अभी भी साबुन, शैंपू, तेल, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर आदि बेचकर देश का धन विदेश ले जा रहे हैं।

पतंजलि द्वारा भारत माता एवं सनातन की सेवा

पतंजलि ने 30 वर्षों में लगभग एक लाख करोड़ रुपये से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान से लेकर, चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के कार्यों द्वारा भारत माता की सेवा की है और यह सेवा यज्ञ अखण्ड रूप से चल रहा है।

इस गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी का व्रत लेकर पतंजलि के श्रेष्ठतम स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाकर एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं और आर्थिक लूट व गुलामी से देश को बचायें। देश का पैसा देश में रहे और देश सेवा में लगे, यही हमारे स्वदेशी अभियान का मूल सिद्धांत है। हमने पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाकर Prosperity for Charity का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है।

**महाकुंभ पर सनातन का संकल्प**

सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं एकता, समानता, आचरण की शुचिता, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, सद्भावना, वेद निष्ठा, गुरु निष्ठा एवं भगवान के सनातन सांस्कृतिक संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक संविधान में पूर्ण निष्ठा।

जाति, वर्ग, समुदाय आदि के नाम पर किसी भी प्रकार का ऊंच-नीच, भेदभाव, पक्षपात, पाखंड, अंधविश्वास सनातन धर्म में नहीं है। हमें महाकुंभ पर्व पर सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को 100% मानने, जीने एवं बढ़ाने के लिए संकल्पित, संगठित एवं समर्थ होकर सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने हेतु अपना सर्वस्व आहूत करना है और संगठित रूप से चल रहे सनातन के विरोध का सभी दिशाओं से प्रतिकार भी करना है।

**महाकुंभ के अवसर पर कार्ष्णि आश्रम में पूज्यपाद स्वामी गुरु शरणानन्द महाराज जी के सानिध्य में**

निःशुल्क योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर

**स्थान- श्री गुरुकार्ष्णि कुम्भ मेला शिविर, सलौरी, सेक्टर-9, गंगेश्वर मार्ग, प्रयागराज**

**सम्पर्क करें : 8954555999**

**27 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रातः 5:00 से 7:30 बजे**

संगम स्नान के साथ योग-ध्यान के पुण्य से जीवन का सौभाग्य जगाएं।

## ट्रम्प द्वारा चयनित नये डिफेंस मंत्री के "सलैक्शन" को कमजोर माना जा रहा है

सेना विशेषज्ञ, नये डिफेंस मंत्री में "अनुभव" व नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता की कमी देख रहे हैं

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जनवरी। ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को नियुक्त करने की आदत है, जिनमें न तो अनुभव है और ना ही नेतृत्व क्षमता। पीट हैगसेथ ऐसे ही व्यक्ति हैं, जिन्हें डिफेंस सैक्रेटरी (रक्षा मंत्री) बनाया गया है। फॉक्स न्यूज़ के पूर्व होस्ट व पूर्व सैन्य अधिकारी रहे पीट को ट्रम्प ने रक्षा मंत्री बनाया है। सोनेट में एक वोट के अंतर से उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिली। टाई होने पर यह वोट उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंन्स ने दिया था।

हैगसेथ की नियुक्ति विवादों से घिरी है, उनकी शैक्षणिक योग्यता और पूर्व आचरण के आधार पर चिंता जताई

अमेरिका के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, "डिफेंस मंत्री" को राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर की वरीयता दी जाती है, डिफेंस के मामलों में तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन भी किसी सैन्य कार्यवाही से पूर्व, डिफेंस मंत्री के मार्फत, राष्ट्रपति से इजाजत लेकर आगे कार्यवाही करते हैं।

नये डिफेंस मंत्री एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं, वे वरिष्ठ टी.वी. कॉमेंटेटर रहे हैं, वे एक सेना में भी रहे हैं तथा इराक व अफगानिस्तान सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन सैन्य रणनीतिकार नहीं रहे हैं।

का रही है कि क्या वे के इस पद के उपयुक्त हैं। पीट के आलोचक रक्षा क्षेत्र और नीति निर्माण में उनके कम अनुभव के आधार पर उन्हें अमेरिका के रक्षा सचिव के पद के उपयुक्त नहीं मानते हैं। हैगसेथ जब सेना में थे, तब इराक व अफगानिस्तान में तैनात रहे थे, उन्हें जमीनी क्षेत्र का अनुभव तो है, पर रक्षा मंत्रालय चलाने के लिए जिस रणनीतिक

व प्रशासनिक अनुभव की जरूरत होती है वह उनमें नहीं है।

रक्षा मंत्री के लिए जटिल रक्षा नीतियों पेंटगन के विशाल संसाधनों के बजट प्रबंधन तथा पूरा राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सैन्य रणनीति बनाने की गहरी समझ होने की जरूरत होती है। आलोचक कहते हैं, मीडिया पर्सन का काम कर चुके पीट के पास इस दर्जे के उच्चस्तरीय निर्णय लेने का विवेक नहीं है।

इसके अतिरिक्त, आलोचकों ने हैगसेथ के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ समन्वय करने, सैन्य कूटनीति को संभालने और रक्षा विभाग जैसे बड़े नौकरशाही संगठनों का नेतृत्व करने के लिए उनमें पर्याप्त अनुभव नहीं होने पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)